लेवी चीनी का कोटा घटाने पर विचार

उद्योग ने मांग से ज्यादा उपलब्धता के कारण कोटा कम करने की मांग की

47

लाख टन चीनी लेवी कोटा में उपलब्ध है चालू सीजन में

26

लाख टन चीनी की जरूरत होती है पीडीएस में वितरण के लिए

प्रेट्र ◆ नई दिल्ली

खाद्य मंत्रालय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वितरण के लिए मिलों से लेवी चीनी का कोटा घटाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस समय मिलों को अपने उत्पादन में से 10 फीसदी चीनी लेवी कोटा के रूप में सरकार को देनी होती है। चूंकि सरकार काफी कम भाव पर यह चीनी लेती है, इसलिए मिलें लंबे अरसे से लेवी चीनी कोटा व्यवस्था खत्म करने की मांग करती रही हैं।

लेवी चीनी कोटा व्यवस्था के तहत इस समय सरकार 1900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर मिलों से चीनी ले रही है जबकि खुले बाजार में चीनी का भाव 3000-3200 रुपये प्रति क्विंटल टल रहा है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीनी उद्योग ने लेवी चीनी का कोटा घटाने की मांग की है। मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। उद्योग ने लेवी चीनी का कोटा 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की है, जिससे उसे सस्ती चीनी देने से होने वाले घाटे में कमी आ सके।

उद्योग का कहना है कि पीडीएस के लिए चीनी की सालाना मांग करीब 24-26 लाख टन रहती है। खाद्य मंत्रालय को दिए ज्ञापन में उद्योग ने कहा कि लेवी चीनी का कोटा घटाने की जरूरत है क्योंकि सरकार पिछले कुछ वर्षों में कोटा की पूरी चीनी उठाने में नाकाम रही है। मौजूदा मार्केटिंग वर्ष 2011-12 में लेवी चीनी का बकाया स्टॉक 21 लाख टन तक पहुंच गया है।

ज्ञापन के अनुसार मौजूदा मार्केटिंग वर्ष के शुरू में बकाया 21 लाख टन स्टॉक और इस साल का 26 लाख टन लेवी चीनी कोटा जोड़कर कुल 47 लाख टन चीनी पीडीएस के लिए उपलब्ध होगी। यह उपलब्धता पीडीएस के तहत वास्तविक खपत से काफी ज्यादा है। इसलिए लेवी चीनी का कोटा घटाने की जरूरत है। देश में चालू सीजन में (सितंबर में समाप्त होगा) 260 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि पिछले सीजन में 245 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।